भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ एवं असफलताएँ
[ACHIEVEMENTS AND FAILURES OF INDIA'S ECONOMIC PLANNING]

अथवा

नियोजन के अन्तर्गत भारत का आर्थिक विकास
[ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDIA DURING PLANNING]

भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल, 1951 से प्रारम्भ हुआ तब से अब तक दस पंचवर्षीय योजनाएँ तथा सात वार्षिक योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। इस प्रकार नियोजन के 55 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 55 वर्षों में देश ने निःसन्देह प्रगति की है। कृषि उत्पादन बढ़ा है। उद्योगों का विकास हुआ है। परिवहन और संचार सुविधाओं में वृद्धि हुई है। शिक्षा का प्रसार हुआ है। विदेशी व्यापार के आकार का समुचित विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय आय, घरेलू बचत व विनियोग दरों में भी वृद्धि हुई है। हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं लेकिन अभी भी गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने में सफलता नहीं मिली है।

भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ
(ACHIEVEMENT OF ECONOMIC PLANNING IN INDIA)

विगत् नियोजन काल में भारत की उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं—

1. राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (Increase in National Income and Per-Capital Income)—55 वर्षों के योजना काल में शुद्ध राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों में बराबर वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय 1950-51 में

Scanned with CamScanner

चालू मूल्यों के आधार पर क्रमशः 8,574 करोड़ रुपये व 239 रुपये थी जो 2004-05 में बढ़कर 15,29,366 करोड़ रुपये व 12,414 रुपये हो गयी है। इन आँकड़ों से यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है कि प्रत्येक दृष्टि से आय में वृद्धि हुई है।

2. बचत एवं विनियोग दरों में वृद्धि (Increase in Saving and Investment Rates)—इस दौरान शुद्ध घरेलू बचत व शुद्ध विनियोग दरों में बराबर वृद्धि हुई है। 1950-51 में घरेलू बचत की दर 5·5 प्रतिशत थी जो 2003-04 में बढ़कर 28·1 प्रतिशत हो गयी है। इसी प्रकार 1950-51 में विनियोग दर 5·5 प्रतिशत थी वह भी बढ़कर 26·3 प्रतिशत हो गयी है।

3. कृषि क्षेत्र में विकास (Progress in Agricultural Sector)—आर्थिक नियोजन के 55 वर्षों में कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जैसे खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 551 लाख टन था वह 2004-05 में बढ़कर 210·44 मिलियन टन हो गया है। इसी प्रकार कपास व जूट का उत्पादन भी इसी अवधि में 24 व 35 लाख गाँठों से बढ़कर क्रमशः 17·1 व 9·7 मिलियन गाँठें हो गयी हैं।

इसी प्रकार सिंचाई सुविधाओं में भी दुगुने से अधिक मात्रा की वृद्धि हुई है। 1950-51 में 2·26 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध थी जबकि अब 2001-02 में यह सुविधाएँ 93·95 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में मिलने लगी हैं।

4. औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति (Progress in Industrial Sector)—आर्थिक नियोजन के 55 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है। सार्वजनिक उद्योगों का भारी विकास हुआ है। उद्योगों में विविधता आयी है। उत्पादन बढ़ा है। जिन उद्योगों का भारत में कोई नाम नहीं था वे उद्योग यहाँ स्थापित हुए हैं। औद्योगिक निर्भरता बढ़ी है।

1950-51 व 2004 के बीच तैयार इस्पात व सीमेण्ट में क्रमशः 14 व 20 गुना, कागज में 18 गुना, साइकिलों में 69 गुना, मशीनरी औजारों में 2,775 गुना व नाइट्रोजन खाद में 811 गुना उत्पादन बढ़ा है।

5. सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार (Expansion of Public Sector)—इस काल में सार्वजनिक क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। 1950-51 में भारत में केवल 5 सार्वजनिक उपक्रम थे और उनमें 29 करोड़ रुपये विनियोजित थे लेकिन 1998-99 के अन्त तक इन उपक्रमों की संख्या 246 हो गयी। इन उपक्रमों में 22 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

6. विद्युत उत्पादन में वृद्धि (Increase in Electricity Production)—प्रथम योजना के प्रारम्भ में विद्युत उत्पादन 23 लाख किलोवाट था जो 1992-93 में बढ़कर 301 विलियन किलोवाट हो गया है। 1955-56 में प्रति व्यक्ति खपत 2·4 किलोवाट थी जो वर्तमान में 42·1 किलोवाट पहुँच गयी है।

7. परिवहन एवं संचार साधनों के क्षेत्र में प्रगति (Progress in Transport and Communi-cation)—योजनाकाल में परिवहन एवं संचार के साधनों में काफी प्रगति हुई है। 1950-51 में 53,000 किलोमीटर रेलमार्ग था जो 2004 में बढ़कर 63·22 हजार किलोमीटर हो गया है। इसी प्रकार 1950-51 में 4 लाख किलोमीटर लम्बी सड़कें थीं जबकि आज इन सड़कों की लम्बाई 33 लाख किमी. है।

Scanned with CamScanner

1950-51 के अन्त में जहाजरानी की क्षमता 3·7 लाख GRT थी जो अब बढ़कर 62·8 GRT हो गयी है।

1950-51 में कुल 36000 डाकखाने थे लेकिन आज इनकी संख्या एक लाख 50 हजार तीन सौ छियालीस है। इसी प्रकार 1950-51 में 1·7 लाख टेलीफोन देश में थे, लेकिन आज इनकी संख्या 60 लाख से अधिक है।

8. शिक्षा का प्रसार (Expansion of Education)—योजना आरम्भ करते समय देश में 27 विश्वविद्यालय थे लेकिन आज इनकी संख्या 146 है। 1951 में देश की साक्षरता 16·6 प्रतिशत थी जो 2001 में बढ़कर 64·8 प्रतिशत हो गयी है।

9. आयात एवं निर्यात में वृद्धि (Increase in Imports and Exports)—इस 55 वर्ष के आर्थिक नियोजन में आयात एवं निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1950-51 में आयात एवं निर्यात क्रमशः 608 से 606 करोड़ रुपये के थे जो 2004-05 में बढ़कर क्रमशः 106·12 अरब डॉलर व 79·60 अरब डॉलर के हो गये हैं।

10. बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति (Progress in Banking Sector)—देश में बैंकिंग सेवा का काफी विस्तार किया गया है। दिसम्बर 1951 में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या 2647 थी जो 30 जून, 2002 के अन्त में बढ़कर 60649 हो गयी है।

11. स्वास्थ्य एवं समाज सेवाएँ (Health and Social Welfares)—स्वास्थ्य एवं समाज सेवाओं में भी काफी प्रगति हुई है। 1950-51 में देश में 30 मेडिकल कॉलेज थे लेकिन आज इनकी संख्या 128 है। पहले मलेरिया, टी. बी., चेचक व प्लेग आदि से हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। मृत्यु दर जो 1950-51 में 27·4 प्रति हजार थी वह 2001 में घटकर 8·1 प्रति हजार रह गयी है। इसी प्रकार औसत जीवन जो पहले 23 वर्ष था आज 60 वर्ष से अधिक है। 1950 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी स्वास्थ्य केन्द्र नहीं था लेकिन आज 22,243 से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र व 12,999 उपकेन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

भारत में आर्थिक नियोजन की असफलताएँ
(FAILURES OF ECONOMIC PLANNING IN INDIA)

पिछले 55 वर्ष के आर्थिक नियोजन से देश में काफी प्रगति हुई लेकिन इन सभी उपलब्धियों के बावजूद पहले से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। अतः आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि नियोजन असफल रहा है। **डॉ. के. एन. राज** (Dr. K. N. Raj) का कहना है कि नियोजन काल में देश में आय एवं सम्पत्ति की असमानता बढ़ी है तथा भारत की अर्थव्यवस्था में समाजवादी तत्वों की अपेक्षा पूँजीवादी तत्वों का बाहुल्य बना हुआ है। इस प्रकार भारत में आर्थिक नियोजन की कुछ समस्याएँ हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

1. प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति (Slow Progress of Per Capital Income)—भारत में आर्थिक नियोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हो रही है।

2. क्षेत्रीय असन्तुलन (Regional Imbalance)—नियोजन के फलस्वरूप क्षेत्रीय

Scanned with CamScanner

भी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्य पिछले राज्य बने हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य आज भी विकसित हैं और नियोजन से पूर्व भी विकसित थे।

3. मूल्य वृद्धि (Price Rise)—नियोजन काल में घाटे की अर्थव्यवस्था होने से मूल्य वृद्धि होती है लेकिन भारत में यह मूल्य वृद्धि आवश्यकता से अधिक रही है।

4. बेरोजगारी में वृद्धि (Increase in Employment)—आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों में एक उद्देश्य बेरोजगारी में कमी करना रहा है लेकिन नियोजन काल में बेरोजगारी में बराबर वृद्धि होती रही है। बेरोजगारी कितनी है, इस सम्बन्ध में विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु यह निश्चित है कि हर योजना में अन्त में बेरोजगारी कम होने के बजाय बढ़ती ही गयी है। जहाँ प्रथम योजना के प्रारम्भ में 33 लाख व्यक्ति बेकार थे वहाँ वर्तमान में लगभग 5 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार होने का अनुमान है।

5. आय एवं धन की असमानता में वृद्धि (Advancement in the Inequality of Income and Wealth)—आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक केन्द्रीयकरण को समाप्त कर आर्थिक समानता में वृद्धि करना रहा है। लेकिन नियोजन के 55 वर्षों के पश्चात् भी धनी व्यक्ति अधिक धनी व गरीब व्यक्ति अधिक गरीब हो गया है। आय व धन की असमानता बढ़ी है। **डॉ. के. एन. राज** के अनुसार, "आय व सम्पत्ति की असमानता बढ़ी है।"

6. सार्वजनिक उद्योग की असफलताएँ (Failures of Public Enterprises)—इस समय देश में केन्द्रीय सरकार के 246 उपक्रम हैं जिनमें 135871 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है लेकिन अनेक अक्रम हानि पर चल रहे हैं। इसके कारण हैं—यह अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन भत्ते अधिक हैं। इनके पास स्टाक अधिक रहते हैं। प्रबन्धकों में प्रबन्धकीय योग्यता की कमी है क्योंकि वे पेशेवर न होकर सरकारी अफसर हैं। अतः सार्वजनिक उद्योग आशा के अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहे हैं।

7. विदेशी सहायता पर निर्भरता (Dependence on Foreign Aid)—भारतीय आर्थिक नियोजन की विफलता का एक कारण विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता भी है। **प्रो. बी. आर. शिनॉय** (Prof. B. R. Shenoy) के अनुसार, "विदेशी सहायता का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पाया है, क्योंकि साधनों के एक बड़े भाग का उपयोग विशाल नदी-घाटी योजनाओं या अनुत्पादक औद्योगिक इकाइयों में किया गया है।" समय-समय पर विदेशी सहायता रोक लिये जाने से देश के आर्थिक नियोजन में गतिरोध पैदा हो गया था जिसके फलस्वरूप योजनाओं को स्थगित करना पड़ा था। भारत पर मार्च 1993 के अन्त में 2,19,169 करोड़ रुपये विदेशी ऋण भार था। जिसे आज **अनिवासी भारतीयों** (N.R.Is.) के सहयोग से कुछ सीमा तक कम किया जा सका है।

8. लक्ष्य प्राप्ति में असफलता (Failure to Achieves Targets)—विभिन्न योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। इसके प्रमुख कारण निम्नवत् थे—

1. पर्याप्त जन सहयोग का अभाव।

Scanned with CamScanner

2. प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय अयोग्यता।
3. हीनार्थ प्रबन्धन।
4. असन्तोषजनक औद्योगिक सम्बन्ध।
5. ऊँचे लक्ष्य।
6. पर्याप्त पूँजी-निवेश का अभाव।
7. निजी क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्वों का अभाव।
8. भ्रष्ट विनियोजित व्यवस्था।
9. देशी तकनीक के विकास पर बल न देना।
10. अक्षम वित्तीय लोक नीति।

9. दोषपूर्ण नियंत्रण नीति (Defective Control Policy)—इस 56 वर्ष के नियोजन में सरकारी नियंत्रण नीति भी दोषपूर्ण रही है जिससे आर्थिक नियोजन के लाभ प्राप्त नहीं हो सके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर जो नियंत्रण और नियमन लगाये हैं परस्पर असम्बद्ध रहे हैं। प्रत्येक नियन्त्रण ने एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति की लेकिन देश की अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करती रही है।

योजनाओं को सफल बनाने के लिए सुझाव
(SUGGESTIONS FOR THE SUCCESS OF PLANS)

देश के करोड़ निवासियों के रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाने, बेरोजगारी कम करने, प्राकृतिक साधनों का विदोहन करने, आर्थिक विषमता को कम करने तथा समाजवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता है और वह है नियोजन को आगे बढ़ाना। अतः आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं—

1. जनसहयोग (Public Co-operation)—योजना की सफलता के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि जन-सहयोग आवश्यक ही प्राप्त किया जाय। इसके लिए जनता को योजनाओं से परिचित कराया जाय। लाभों को बताया जाय तथा जनता में योजनाओं के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति को त्यागकर योजनाओं में सहयोग देने के लिए आकर्षित किया जाय। इसके लिए 'देश की समृद्धि आपकी समृद्धि है।' जैसे नारों का प्रयोग किया जाय।

2. मूल्य स्थायित्व (Price Stability)—योजनाओं की सफलता के लिए दूसरा सुझाव यह है कि मूल्य स्थायित्व लाया जाय। यद्यपि योजनाकाल में मूल्य वृद्धि होती है लेकिन वह सीमित दायरे में ही होनी चाहिए। अत्यधिक मूल्य वृद्धि योजना की लागत बढ़ाती है तथा योजना में लाभों को अप्रभावी कर देती है। इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

3. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में समन्वय (Co-ordination in Public and Private Sectors)—योजनाओं की सफलता के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में उचित [illegible] एवं [illegible] के साथ साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का

Scanned with CamScanner

पर्याप्त विकास भी किया जाना चाहिए। यह दोनों क्षेत्र एक-दूसरे के प्रतियोगी न होकर सहयोगी होने चाहिए। भारत जैसे देश में जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धान्त अपनाया जाता है वहाँ तो इनमें सहयोग एवं समन्वय और भी आवश्यक है।

4. गाँवों में गैर-कृषि क्षेत्र का विकास (Development of Non-agricultural Sector in Villages)—भारत में छः लाख से अधिक गाँव हैं जिनमें 74·3 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि ग्रामीण जनता को गैर कृषि कार्यों में लगाया जाय जिससे कि कृषि पर जनसंख्या का भार कम हो सके तथा कुल उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। इसके लिए गाँवों में गैर कृषि उद्योग धन्धों जैसे कुटीर उद्योग, दुग्ध उद्योग, मुर्गीपालन आदि का विकास किया जाना चाहिए जिसके लिए वित्तीय एवं तकनीक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

5. बचतों एवं विनियोगों को प्रोत्साहन (Incentive to Savings and Investments)—देश में पूँजी निर्माण की दर को गति देने के लिए यह आवश्यक है कि बचत एवं विनियोगों को प्रोत्साहित किया जाय। इसके लिए व्ययों में छूट की जानी चाहिए।

6. केन्द्र व राज्यों के बीच मधुर सम्बन्ध (Good Relation between the Centre and the State)—भारत एक संघीय राष्ट्र है जहाँ केन्द्र व राज्यों के बीच विभिन्न उत्तरदायित्वों का बँटवारा संविधान के अन्तर्गत किया गया है। आर्थिक नियोजन सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए किया जाता है। अतः केन्द्र व राज्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए।

7. पूँजी प्रधान एवं उपभोग प्रधान उद्योगों में समन्वय (Co-ordination among Capital Industries and Consumption Industries)—योजनाओं की सफलता के लिए पूँजी प्रधान एवं उपभोग प्रधान उद्योगों में समन्वय होना चाहिए जिससे कि राष्ट्र आत्मनिर्भर बने तथा जनता की उपभोग सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर हो सके।

8. कुशल प्रशासन एवं मूल्यांकन (Efficient Administration and Evaluation)—आर्थिक नियोजन को कार्यरूप में परिणित करते समय उनका प्रशासन कुशलता से किया जाना चाहिए। हर स्तर पर मितव्ययिता तथा बर्बादी का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही समय-समय पर योजनाओं का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए जिससे कि गलतियों को तुरन्त ठीक किया जा सके।

9. वास्तविक एवं व्यावहारिक नीतियाँ (Real and Practical Policies)—नियोजन की सफलता के लिए वास्तविक एवं व्यावहारिक नीतियाँ निर्धारित की जायें जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

10. मानव शक्ति का उपयोग (Utilisation of Man Power)—योजनाएँ इस प्रकार की होनी चाहिए कि उन योजनाओं में उपलब्ध मानव शक्ति अधिकाधिक लगायी जा सके। इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा।

11. अन्य सुझाव (Other Suggestions)—उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त कुछ सुझाव निम्नवत् हैं—

(i) प्रशुल्क एवं मौद्रिक नीति में उचित समन्वय होना चाहिए।

(ii) प्रशासन व्यवस्था को [illegible]

Scanned with CamScanner

(iii) विदेशी निर्भरता समाप्त की जाय।

(iv) साधनों को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाय।

(v) नियोजन को सफल बनाने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण किया जाय।

निष्कर्ष (Conclusion)

नियोजन का वर्ष सफलताओं और असफलताओं का मिश्रण है। इसमें दो राय नहीं है कि औद्योगिक उत्पादन में आशा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है। विकास दर धीमी रही है। बेरोजगारी कम होने के स्थान पर बढ़ी है। लेकिन इस अवधि में देश ने बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है। वास्तव में, इन योजनाओं से कुछ सफलता मिली है, नये-नये उद्योग स्थापित हुए है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। कृषि उत्पादन बढ़ा है। सामाजिक सुविधाओं का विकास हुआ है। प्रति व्यक्ति आय एवं रहन-सहन का स्तर ऊपर उठा है। लेकिन यदि नियोजन की विफलताओं को ध्यान में रखकर कुछ और प्रयास किये जायें तो नियोजन से और अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

Dr.Piali Biswas

Scanned with CamScanner